

BIHAR STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY

बुद्ध मार्ग, पटना / BUDH MARG, PATNA - 800 001

Email address- bslsa\_87@yahoo.in / PHONE: 2230943 (O) FAX : 0612-2201390

Patron-in-Chief

Hon'ble the Chief Justice  
Patna High Court, Patna

Hon'ble Executive Chairman

Hon'ble Mr. Justice  
Shiva Kirti Singh

Patna High Court, Patna

Radha Krishna

Member Secretary

पत्रांक/LETT.No.

दिनांक/DATE

981

16-05-2012

To,

The District & Sessions Judge-cum-Chairman,  
District Legal Services Authority,  
Rohtas at Sasaram.

Ref:- Your Letter No.97 dated 24.04.2012

Sub:- Guidelines in respect of appointment of Staffs on Contract basis.

Sir,

As directed I inform your goodself that Draft of Guidelines was placed before His Lordship and His Lordship has been pleased to approve the guidelines and copy of which is enclosed with this letter to be followed.


So far payment of increment to contract staff is concerned in this regard correspondence is being made with the Law Department for clarification as to whether consolidated payment of emolument increasing time to time adding of increment as per Govt Notification or only initial stage of pay will be made along with DA and other allowances in the shape of consolidated amount meaning thereby there will ever be no increment to such staff so which one be followed may kindly be clarified.

This is for your goodself information and needful

Thanking you.

Encl:-One sheet.

Yours faithfully



(Radha Krishna)

Member Secretary

Bihar State Legal Services Authority

Copy to - All the Dist. & Sessions Judges-cum-chairmen,

DLSAs of State of Bihar for information and needful

**विषय:- संविदा के आधार पर नियोजन के मार्ग दर्शक सिद्धान्त**

विभिन्न जिला विधिक सेवा प्राधिकारों/स्थायी लोक अदालतों में संविदा के आधार पर नियोजन हेतु स्वीकृत पदों पर भर्ती की गयी है। इस भर्ती में सामान्यतः बिहार सरकार, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प - ज्ञाप सं० 3/एम.-78/2005-का० 2401/पटना, दिनांक 18.07.2007 में दी गयी प्रक्रिया एवं मार्ग दर्शक सिद्धान्तों का अनुपालन किया गया है। कुछ जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकारों द्वारा उक्त संकल्प के कंडिका 4, जिसमें संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को समेकित (Consolidated) पारिश्रमिक के भुगतान का प्रावधान है तथा एकरारनामों के कंडिका 2, जिसमें संविदा की अवधि की शर्त है, के संबंध में दिशा-निर्देश मांगा गया है।

उक्त के संबंध में सम्यक विचारोंपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिया गया है-

- (1) आगे की कंडिकाओं के अध्वधीन संविदा के आधार पर नियोजन के संबंध में सामान्यतः बिहार सरकार, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के उक्त संकल्प- ज्ञाप संख्या 3/एम०-78/2005-का०-2401/पटना, दिनांक 18.07.2007 में दिये गये मार्ग दर्शक सिद्धान्तों का अनुपालन- किया जायेगा।
- (2) जिला विधिक सेवा प्राधिकार/ स्थायी लोक अदालत में संविदा पर नियुक्ति अस्थायी प्रोजेक्ट के अन्तर्गत हुई है, जिसकी अवधि निश्चित नहीं है तथा बिना पूर्व सूचना के यह कभी भी समाप्त हो सकती है। अतः माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देश के आलोक में यह नियोजन संविदा के आधार पर अगले आदेश तक के लिए किया जायेगा।
- (3) संविदा के आधार पर नियोजित कर्मों को देय पारिश्रमिक का निर्धारण उस पद के प्रारंभिक स्टेज का वेतनमान, महंगाई वेतन, महंगाई भत्ता तथा सभी अन्य श्रेणी के भत्ते जैसे मकान भाड़ा-भत्ता को मिलाकर किया जायेगा। उक्त को मिलाकर जो समेकित (Consolidated) राशि आवेगी उसका भुगतान नियोजित कर्मों को किया जायेगा।
- (4) संविदा पर नियोजित कर्मों का एकरारनामा प्रत्येक वर्ष नवीनीकृत किया जायेगा। नवीनीकृत किये गये एकरारनामा को राज्य प्राधिकार से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। अनुमोदन की केवल तब आवश्यकता होगी जब किसी भी कारण से संविदा को नवीनीकृत नहीं किये जाने का प्रस्ताव हो। राज्य प्राधिकार के निर्देश/आदेश या अनुमोदन से ही संविदा के नवीनीकरण से इन्कार किया जायेगा अन्यथा नहीं। एकरारनामा नवीनीकृत किये जाने के समय नियोजित कर्मों को देय पारिश्रमिक का पुर्ननिर्धारण उपर्युक्त कंडिका 3 के अनुसार किया जायेगा।
- (5) संलग्नक-1 में विहित प्रपत्र में एकरारनामा सम्पन्न किया जायेगा।

सदस्य सचिव  
बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार,  
पटना